ग्रामीण नवयुवकों को स्व–रोजगार के प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना का प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह द्वारा उद्घाटन

स्थान : दिल्ली दिनांक : 15–8–1979

मान्य उपराज्यपाल जी, भानुप्रताप सिंह जी और दोस्तो, मुझको इस अवसर पर आपके यहां आने में बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि ये काम जो आप करने जा रहे हैं या जिस विषय में समारोह हुआ, उसमें मेरा बहुत मन है, वह मेरे मन के अनुकूल है, मेरे चिन्तन के अनुकूल है। मैं बहुत दिनों से इसी विचार का रहा हूँ जिस विचार को आप कार्य–परिणत करने जा रहे हैं। भाई यह तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको आप बन्द करो, भईया। क्या रखा है इन बातों में। बस अब मत इसको करना। हॉ, यह न मालूम कहॉ से–––––––––––––––––

सज्जनो, मैं इस वक्त जो कहने जा रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक प्राइवेट नागरिक की हैसियत से कहूंगा। उसकी वजह यह है कि जो मेरे विचार है, अभी अपने साथियों के सामने रखे नहीं हैं। वो मुझसे सहमत होंगे या नहीं होंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ। मुझे डर यह है कि शायद वो सहमत मुझसे नहीं होंगे और मैं कह जाऊं कि साहब प्राईम मिनिस्टर ने डिकलेयर कर दिया, यह ठीक नही है। मैं कोशिश करूँगा कि वो लोग सब धीरे–धीरे मेरे विचार के हो जायें और अगर मुझको वो सफलता हो जाती है, तो मैं समझूंगा कि वाकई सही माने में देश की कोई सेवा हुई, वरना यह सेवा मैं या मेरे हमख्याल लोग, मेरे जैसे विचार रखने वाले लोग, उनकी दष्टि में हो नहीं पायेगी। इस गरीब देश को।

भानुप्रताप सिंह जी का यह विचार था कि गांवों के पुनर्निर्माण का एक अलग विभाग कायम हो। उन्होंने बतला ही दिया। जैसे ही उन्होंने कहा मैंने स्वीकार कर लिया। उनकी और मेरी वैवलैंथ, इसकी हिन्दी क्या होगी जी? मतलब है कि विचारधारा तो खैर नहीं होता, वह तो आडियोलॉजी होती है। मतलब बिल्कुल इस मामले में। वैसे अधिकतर लोगों का, जो कि गांवों से सम्बंध रखते हैं, वो एक है। बहुत दिनों से, मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ। वो बहुत अच्छे किसान हैं, खेती करते रहे हैं, उनके छोटे भाई भी अलग उनसे खेती करते थे। फिर वो कनाड़ा चले गये और उनके पिता जी हमारे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर्स थे। तो खेती के प्रति प्रेम, यह हर किसान के मन में होता ही है लेकिन भानुप्रताप सिंह जी इस मामले में और ज्यादा लोगों से आगे बढ़े हुए हैं। वो चिंता करते हैं कि गरीबी कैसे मिटे, किसान, गांव, खेती, बराबर उनका चिन्तन यही रहता है। तो इसलिए उनका इस समारोह के लिए जो मेरे पास निमंत्रण–पत्र आया तो मैंने बहुत खुशी से इसे स्वीकार कर लिया।

अब मैं चंद बातें आपके सामने, जिनको मैं बुनियादी, मौलिक समझता हूँ, रखना चाहता हूँ। जैसा मैंने आज सवेरे कहा था कि इस ध्वजारोहण समारोह में, तीन समस्याएं देश की– देश की गरीबी कैसे मिटे, बेरोजगारी कैसे मिटे और गरीब–अमीर का अंतर, जो खाई चौड़ी होती जा रही है बजाए कम होने के – वो कैसे कम हो? चौथी और कही जा सकती है कि जनतंत्र की भावना हमारे यहां कैसे प्रबल हो? अब मेरा ख्याल यह है कि छोटी इकाइयां, थोड़ी–थोड़ी जमीन लोगों पर हो। कृषि क्षेत्र में भी छोटी इकाई और औद्योगिक क्षेत्र में भी छोटी इकाई या गृह उद्योग या जो काम हाथ से नहीं हो सकता, मशीन से हो तो छोटी–छोटी मशीनों के जरिये चलने वाला उद्योग। इन उद्योगों से और इकाइयों से हमारे जो चार उद्देश्य हैं, वो चारों पूरे हो जाते हैं। गरीबी का मतलब है धन–दौलत की कमी।

धन–दौलत माने सिक्के नहीं, उस सामग्री से है, जिनके इस्तेमाल करने से मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो इस तरह का धन या सामान ज्यादा पैदा होगा छोटी इकाइयों में, ज्यादा रोजगार मिलेगा, गरीबी–अमीरी का अन्तर कम होगा और एक प्रजातांत्रिक भावना देश में पैदा होगी, ऐसा मेरा ख्याल है।

मोटा सा सिद्धांत है अर्थशास्त्र का कि उत्पादन के साधनों में जो सीमित हों, कम हों तो हमारी अर्थव्यवस्था उस क्षेत्र में ऐसी हो कि उस साधन का बेहतरीन उपयोग हो सके– चाहे दूसरे साधन वैस्ट ही क्यों न हो जायें या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल क्यों न हो जायें। दूसरे शब्दों में यह खेती को लीजिए। तीन उत्पादन के साथ हैं– भूमि, काम करने वाले श्रमिक और पूंजी। तो हमारे यहां काम करने वालों की कमी नहीं है। पूंजी कम है बेशक, पूंजी के माने यह है कि बैल, हल, खाद–पानी आदि–आदि। जितना होना चाहिए उतनी नहीं है। लेकिन फिर भी बढ़ सकते हैं,कैपीटल की बढ़ोत्तरी हो सकती है, पूंजी–खेती के क्षेत्र में। लेकिन जो तीसरा साधन है भूमि, उसका कोई इलाज नहीं है। अभी जैसा कि कोहली साहब ने कहा, वो सीमित है और उसको इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ती जाती है।

35 करोड़ जनसंख्या थी इस देश की, जब अंग्रेज गये सन् 47 में। सन् 51 में 36 करोड़ 13 लाख हुई, सन् 56 में 45 करोड़ 90 लाख हुई, सन् 61 में 54 करोड़ 70 लाख हुई, में और अब 65 करोड़ के लगभग है। तो यह आबादी 35 करोड़ से 65 करोड़ हो गयी है लेकिन भूमि जितनी कुदरत ने हमको दी थी, वह उतनी हो है। तो अब जैसे–जैसे आबादी बढ़ती जायेगी, हमारे किसानों के पास जो जमीन है, उसका क्षेत्रफल कम होता जायेगा। सन् 70–71 के सेन्सस के अनुसार 33 फीसदी लोगों के पास, जो किसान कहलाते हैं, आधा हेक्टेयर से कम जमीन है, आधा हेक्टेयर नहीं है। आधा हेक्टयर तक है। इसका मतलब है दो बीघे से कम है। और 18 फीसदी के पास आधा हेक्टेयर से एक हेक्टेयर, दो बीघे से चार बीघे और 19 फीसदी किसानों के पास एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर, चार बीघे से आठ बीघे। तो यह हाल है। तो ये नाममात्र के किसान हैं, फिर भी किसान की कोटि में आते हैं। तो भूमि इतनी कम है। हमको कृषि क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था कायम करनी है, जो हमारी कम भूमि है, उसका बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल हो सके। उसकी पैदावार ज्यादा बढ़ सके और वो पीजेन्ट प्रोपराईटशिप। थोड़ी–थोड़ी जमीन, एक फैमिली या व्यक्ति उसका मालिक हो और वो उसमें मेहनत करे। और किसी के पास बड़ा फार्म न हो। हमारे यहां बहुधा वो एक बात हो जाती है लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ। जितने बड़े–बड़े मैकेनाइज्ड फार्म आपको दिखते हैं, यंत्रीकृत, बड़ी–बड़ी मशीनें चल रही हैं, ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, ये अंग्रेजों के जमाने में नहीं थे। थोड़े–बहुत होंगे, बहुत थोड़े। यह स्वराज होने के बाद कायम हुई हैं। जमींदारी खात्मे की बात चली, सीलिंग लगाने की बात चली, तो छोटे–छोटे लोगों को बेदखल कर दिया जमींदारों ने और गवर्नमेंट उनकी रक्षा नही कर पाई। और बाहर से ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, हारवेस्टर मंगाकर, थ्रेशर कम्बाइड वगैरह, बड़े–बड़े फार्मों में खेती होती है। यह पहले नहीं था। अब बड़े फार्म नहीं हो सकते हैं, जहां आदमी कम हों, जमीन ज्यादा हो। हमारे यहां नहीं है। अमेरिका और आस्ट्रेलिया में जमीन ज्यादा आदमी कम हैं। जमीन इतनी पड़ी है कि जो घेरना चाहे घेर ले, तो वहां ट्रैक्टर चला। अमेरिका का और आस्ट्रेलिया का, कनाड़ा का या और देशों का , जहां कि मनुष्य जनसंख्या को देखते हुए भूमि का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, वहां की गवर्नमेंट का मकसद यह होना चाहिए कि फी व्यक्ति लाभ कैसा हो। फी व्यक्ति पैदावार

कैसे बढ़ायें और जहां प्राकृतिक साधन कम हैं और मशीन कम है, जनसंख्या ज्यादा है, वहां उस मुल्क की गवर्नमेंट का ऐम, उद्देश्य यह होना चाहिए कि फी बीघे जमीन की फी इकाई पैदावार कैसे ज्यादा हो। तो हम इस दूसरी कोटि में आते हैं। जमीन कम है, आदमी ज्यादा हैं। लिहाजा हमारा मकसद, हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारा ऐम यह होना चाहिए कि ऐसी अर्थव्यवस्था कायम हो कि जिससे फी बीघे पैदावार बढ़े। तो थोड़ी–थोड़ी जमीन और आपको भानुप्रताप सिंह जी ने बताया कि फिलीपाईन्स है, साउथ कोरिया है और एक–दो मुल्क और हैं जहां जमीन बहुत कम और पैदावार फी इकाई, फी बीघे, फी एकड़ बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब औद्योगिक क्षेत्र में दो उत्पादन के साधन हैं– पूंजी और श्रम। तो श्रम की तो कमी नहीं है देश में, जरूरत से ज्यादा है। पूंजी के मुकाबले श्रम ज्यादा है, पूंजी की कमी है। तो औद्योगिक क्षेत्र में हमारी व्यवस्था ऐसी हो कि पूंजी की फी इकाई पैदावार ज्यादा हो। वो है कॉटेज इंडस्ट्री, गृह उद्योग, बजाए बड़े कारखानों के।

आप एक बात अपने मन से निकाल दीजिए और फिर सारे मसले हल हो आते हैं कि मशीन क इस्तेमाल करने से कोई पैदावार बढ़ती है– चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र हो– वो ख्याल गलत है। 'इट इज ए फैलेसी' नहीं बढ़ते, हमारे यहां मुगालता हो रहा है। हमारे इकोनॉमिस्टों ने यही पैदा किया हुआ है कि साहब ट्रैक्टर इस्तेमाल हो तब पैदावार बढ़ जायेगी। बड़ा कारखाना आये या बड़ी मशीन लगा दी जाये तो पैदावार बढ़ जायेगी। नहीं बढ़ेगी बल्कि कम होगी। फी व्यक्ति पैदावार बढ़ती है, फी बीघे नहीं बढ़ती और फी रुपया नहीं बढ़ती। फी व्यक्ति बढ़ती है और हमारा मकसद है फी बीघे पैदावार बढ़ाना और जो पूंजी हम लगायें फिक्स्ड इनवेस्टमेंट, उसके फी रुपया, फी इकाई पैदावार बढ़ना, वो मशीन से नहीं बढ़ती। लेकिन यही कनफ्यूजन सबके मन में है कि साहब मशीन लगाओ पैदावार बढ़ जायेगी, देश मालदार हो जायेगा। नहीं, बिल्कुल गलत है। वो फी वर्कर, फिर दोहरा रहा हूँ, एक किसान ट्रैक्टर इस्तेमाल करेगा तो फी किसान पैदावार बढ़ जायेगी लेकिन जमीन कहां से आयेगी, क्योंकि ज्यादा जमीन को कंट्रोल कर सकता है। सौ एकड़, पचास एकड़ को वो दो ट्रैक्टर से कंट्रोल कर सकता है लेकिन हमारे पास तो इतनी जमीन नहीं है लिहाजा हमारा ब्रेक फार्मिंग होगा। बैला के जरिये खेती होगी और कुछ दिनों के बाद, जमीन इतनी कम हो गयी है कि हाथों के जरिये खेती होगी। नहीं हैं बैल जापान के अन्दर, जिसकी पैदावार फी बीघे दुनिया में सबसे ज्यादा है। बैल तक नहीं हैं वहां। तो इसलिए ट्रैक्टर आदि साधनों का इस्तेमाल होता है। बड़े कारखाने ही हमारे देश में होते हैं। बड़े कारखाने होंगे, उस काम को करने के लिए जो छोटे पैमाने और हाथ के जरिये न हो सके। हवाई जहाज बनाने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, इस्पात पैदा करने के लिए, रेलवे के इंजन बनने के लिए और हमारे फौज के जरूरी साज–ओ–सामान को बनाने के लिए।

एक दफे गांधी जी व्याख्यान दे रहे थे। बड़ी फैक्टरियों के खिलाफ और साथ ही यह भी सबको मालूम था कि गांधी जी ये जो सिंगर सीविंग मशीन है, इसके बहुत प्रशंसक थे। वे कई बार कह चुके थे कि मैं यह चाहता हूँ कि ये सिंगर सीविंग मशीन हर घर में हो। मालदार घर है तो मालदार घर की मां की या गृहणी की भी जिम्मेदारी रहे कि अपने बच्चों के कपड़े खुद सिये बजाए दूसरों से सिलवाने के, बजाए खाली बैठे रहने के या बजाए सिनेमा देखने के। और गरीब घर की मालकिन है या विपत्ति आ गयो है तो पड़ोसियों के बच्चों के कपड़े सी कर वो अपना गुजर कर सकती है। तो एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने कहा, "महात्मा

जी यह तो बड़ी फैक्टरी से बनती है।'' फैक्टरी से बनेगी, लुहार तो बना नहीं सकता इसको, सीविंग सिंगर मशीन को और`आप फैक्टरी के खिलाफ कह रह हैं।'' तो महात्मा जी ने कहा, ''मैं हर फैक्टरी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि लुहार नहीं बना सकता तो फैक्टरी लगाओ सिंगर सीविंग मशीन के लिए।'' तो उनकी निहायत रेशनलिस्टक, निहायत रिजनल, निहायत उचित, बुद्धि के अनुकूल, उनकी सारी फिलॉसफी थी। लोगों ने कहा कि साहब आप बिजली के खिलाफ हैं। तो उन्होंने कहा, ''मैं बिजली के खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि बिजली घर-घर हो जाये और बिजली से काम हो लेकिन शर्त यह है कि इस प्रकार से बिजली लगे कि बेरोजगारी न बढ़े।'' उन्होंने अनेक बार कहा। लिहाजा जो लाग गांधी जी को कहते हैं कि साहब रिएक्शनरी थे, तरक्की नहीं करना चाहते थे, बिजली वगैरह के खिलाफ थे, वो अज्ञानी हैं। महात्मा जी आज ही रैलीवेंट नहीं हैं अपने देश में कि आज हमको जरूरत है। महात्मा जी की जो शिक्षा थी वो सन् 2000 में भी रैलीवैंट होगी आर वो दो हजार पचास में भी रैलीवेंट होगी, जैसे समय बीतता जायेगा।

तो यह जो छोटे उद्योगों की बात है, अब ये कॉटेज इंडस्ट्री जिसे कहते हैं या कुटीर उद्योग कहते हैं, इसकी परिभाषा मैं यह करता हूँ कि जो काम हाथ से हो सकता हो और जो एक फैमिली के जरिये होता हो। बस। जिसमें हार्ड वर्क न हो। हो तो ज्यादा से ज्यादा दो-एक। एक से ज्यादा न हो। हमारे यहां इस तरह का कानून बनना चाहिए कि जो काम हाथ से हो सकता है उसके बनाने के लिए मशीन नहीं लगेगी, याद रखो। (तालियां) और जो काम छोटी मशीन से हो सकता है उसके लगाने के लिए, बनाने के लिए बड़ी मशीन नहीं लगेगी। तब जाकर उद्योग-धंधे पनपेंगे, वरना नहीं। मशीन से बना हुआ सामान सस्ता होता है, फायनेंशनली चीपर होता है, बनिस्पत हाथ से बने हुए सामान से।

जब अंग्रेज यहां आये थे तो हमारे यहां सन् 1801 के आसपास के आंकड़े मिलते हैं। 25 फीसदी आदमी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में लगा हुआ था। लफ्ज डोमेस्टिक इंडस्ट्री है यानि घरों में जो होता था काम, वही कुटीर उद्योग है। दुनिया के सारे ही काम तो होते थे। साथ ही मुर्शिदाबाद में और कोटा में हथियार बनाने के लिए, तोपखाने बनाने के लिए, कारखाने भी थे, उसी जमाने में लेकिन और सब काम हाथ से होते थे। 25 फीसदी; 60 फीसदी आदमी खेती करता था और पन्द्रह फीसदी आदमी लगे हुए थे परिवहन में, दुकानदारी आदि के और बहुत से काम हैं, उनमें लगे हुए थे। अब क्या है? अब 72 फीसदी आमदनी खेती मं लगा हुआ है, 60 से 72 और उद्योग-धंधें में 25 से 10 फीसदी। मैंने जैसे आज कहा कि सैन्सेस रिपोर्ट उठाकर पढ़ो अपने देश की। सन् 51 में दस फीसदी आदमी इंडस्ट्री में लगे हुए थे। सन् 61 में दस फीसदी लगे हुए थे। सन् 71 में भी दस फीसदी लगे हए थे। जिस देश में खेती करने वालों की तादाद ज्यादा हो और गैर-जराती, नॉन एग्रीकल्चर ऑक्युपेशन, उद्योग-धंधें में लगे लोगों की तादाद कम हो, वो मुल्क गरीब होता है और गरीब ही रहेगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि खेती छोड़कर लोग दूसरे पेशो में जायें। अब वो कैसे जायेंगे, उस किस्से को मैं यहीं छोड़ देता हूँ। लिहाजा मैं कहता हूँ कि जब 25 देश में फीसदी आदमी लगे हुए थे दूसरे रोजगारों में, तब देश मालदार था। आज देश, सारे देश को कह रहा हूँ बम्बई के, दिल्ली के रहने वाले लोगों का नहीं कह रहा हूँ, सारे देश को कह रहा हूँ और पंजाब के किसानों और हरियाणा के किसानों को मैं कहूँगा।

एक मुश्किल यह है कि दिल्ली पंजाब व हरियाणा के पास बसा हुआ है। पंजाब हरियाणे से लगा लेते हैं तो हिन्दुस्तान भर के किसानों का और गांव के रहने वालों के जीवन स्तर का हिसाब, नहीं हरगिज नहीं। जाओ गंगा पार करो यू0पी0 में। उसके बाद देखो। लखनऊ के आसपास देखो, गोरखपुर और बनारस से सारा बिहार, सारा बंगाल, सारा उड़ीसा, सारा मध्य प्रदेश। गरीबी की सीमा ही नहीं। आप कल्पना ही नहीं कर सकते अगर आप गांव में उधर नहीं गये। मैंने अपनी ऑखों से देखा। अनेक बार, हजार बार देखा कि जवान बहू–बेटियों के पास एक धोती के अलावा दूसरी नहीं है। कुर्ता भी नहीं है, कमीज भी नहीं है, आंगिया भी नहीं है। तो खैर छोड़िये, गरीबी को रोकना तो बहुत दुखदायी एक अध्याय है अपने देश का।

हम चाहते हैं कि लोग खेती छोड़कर दूसरे पेशों में जायें, तब देश मालदार होगा। अच्छा, अब पैदावार ही फी रुपया नहीं बढ़ती, यह छोटे उद्योगों में रोजगार भी ज्यादा मिलता है। मशीन लगाने का मतलब क्या है। मशीन लगाने का मलतब यह है कि दस आदमी एक काम को कर रहे हैं, हमने एक छोटी मशीन लगा दी तो दो आदमी काम करने लगेंगे। दस आदमियों को जितनी आज रोटी मिलती है, उन दो को उनसे ज्यादा मिलेगी, अलग–अलग। लेकिन आठ आदमी बेरोजगार हो जायेंगे और एक मशीन का आदमी मालिक पैदा हो जायेगा। बेरोजगारी बढ़ गयी और एक पूंजीपति पैदा हो गया। यही गांधी जी बराबर कहते थे कि कारखानों के लगाने से पूंजीपति बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और कम लोगों को रोजगार मिलेगा क्या? आज कारखने तो बहुत लग गये हैं लेकिन बेरोजगारी नहीं मिटी है। बेरोजगारी बढ़ती जाती है। जैसे साइंस बढ़ रही है, तकनीकी विज्ञान बढ़ रहा है, इलैक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर बढ़ रहे हैं, स्वचालित (ऑटोमेटिक) मशीन सरकती जाती है। इन सबका उद्देश्य यह है कि किस प्रकार की मशीन बनाई जाये कि कम से कम लोगों को एम्पलायमेंट मिले। लेबरों की तादाद कम हो। पूंजी ज्यादा लगायें, मुनाफा ज्यादा हो।

हम लोग जो जनता पार्टी में नहीं, इलैक्शन मेनीफेस्टो में रख दिया कि दस साल के अन्दर हम बेरोजगारी मिटा देंगे; और आज ही मैंने सुबह बतलाया था कि इन 28 महीनों के अन्दर 25 लाख लड़कों के नाम काम दिलाऊ दफ्तर में और ज्यादा दर्ज हो गये हैं, जितने पहले थे। मैंने बहुत कहा, ''कीतरंजुयरल में लिखवा भी दिया वर्किंग कमेटी के कि पहली बातों को छोड़ो। आगे कोई बड़ा कारखाना और मशीन नहीं बनेगी, उस काम के करने के लिए जो छोटे पैमाने पर हो सकता है। लेकिन यह बात ता जहालत की है। मेरी बात तो रियेक्शनरी है, प्रतिक्रियावादी है, वगैरह, वगैरह। हम सब लोग एकदम मशीन चलती हो, उसमें बिजली की चमक–दमक हो, उसमें पढ़े–लिखे लोग, अंग्रेजी बोलने वाले, जेब में हाथ देकर बातें करते हों। कोई मशीन का काम करने वाला न हो, एक कारीगर मशीन खराब हो जाये तो वो और है, इंजीनियर और ओवरसियर खड़ा हुआ, पतलून की जेब में हाथ दिये खड़ा हो, तो हम सोचते हैं देश तरक्की कर रहा है। एक कारखाना लग गया और देश तरक्की कर गया। नो ssss। इससे नहीं तरक्की होती। हमने इक्वेट कर दिया है प्राग्रेस को विद मशीन कि विकास के माने मशीन और मशीन के माने हैं विकास। बिल्कुल गलत। जो चीजें हाथ से नहीं हो सकतीं, बेशक मशीन लगाओ। मैं फिर दोहराता हूँ लेकिन जो चीज हाथ से हो सकती है, उसके लिए मशीन लगाने की क्या जरूरत है? कपड़ा हाथ से बन सकता था, बनता है, उसी की मांग दुनिया में ज्यादा है। उसकी आर्टिस्टिक डिजाइन आप छह महीने में बदल

सकते हैं, तीन महीने में बदल सकते हैं। मशीन में डिजाइन बदलोगे, कपड़े की सारी मशीन करोड़ों रुपये की रद्दी हो जायेगी। दूसरे देशों मं मांग आपके हैण्डलूम प्रोडक्ट्स की है, न कि मशीन मेड प्रोडक्ट की।

गांधी जी कहते थे कि हाथ से क्यों नहीं, वे हाथ से बुनते रहे, हाथ से क्यों न बुनें। लेकिन हम नाम गांधी का लेते रहे और स्वराज्य आने के बाद भी हम मशीनें लगवाते रहे, वीविंग फैक्टरी और स्पिनिंग मिल्स। क्यों, फिर हम गांधी जी का नाम क्यों लें? या उसकी लॉजिक में कौन सी फैलेसी थी जो वो कहते थे कि इससे रोजगार ज्यादा मिलेग, इससे पैदावार ज्यादा होगी और कारखानों के लगाने से बेरोजगारी बढ़ेगी, पूंजीपति बढ़ेंगे लेकिन उस रास्ते पर चलते रहे। बारह आदमी और 25 साल पहले आप दस आदमी लगा लो, हैण्डलूम के जरिये उतना कपड़ा पैदा करते हैं जितना एक टैक्सटाईल मिल में एक वर्कर बनाता है। अब दस लाख आदमी लगे हुए हैं फैक्टरी में, टैक्सटाईल फैक्टरी में, स्पिनिंग मिल्स, वीविंग मिल्स। अगर स्पिनिंग मिल्स को हम रखना भी चाहें, कायम करना चाहें ता शायद पांच–छह लाख लगेंगेवीविंग मिल्स में। अगर हम यह नियम बना दें, कानून बना दें कि हमारे यहां की जो वीविंग मिल्स हैं, टैक्सटाइल मिल्स हैं उनका कपड़ा हिन्दुस्तान में नहीं बिकेगा, बाहर बिकेगा तो जो कपड़ा यह पांच–छह लाख मजदूर कारखानों के जरिये बना रहे हैं इसके बनाने के लिए, साठ–सत्तर लाख आदमी लगेंगे, जो कि हैण्डलूम से उस कपड़े को बनायेंगे। साठ–सत्तर लाख आदमियों को रोजगार मिल गया बिना कुछ करे–धरे, न गवर्नमेंट को पूंजी लगानी, न बिजली देनी न टैक्नीकल कहीं से मंगाना। लेकिन कौन करे?

अंग्रेजों ने हमारी दस्तकारियों को खत्म किया, जहां 25 फीसदी आदमी लगे हुए थे। काहे के इंटरेस्ट में? अपनी यार्कशायर, लंकाशायर, वैस्टलैंड वगैरह के कारखानों को चलाने के लिए। इतना अच्छा कपड़ा हमारे यहां से जाता था इंग्लैण्ड को, जब अंग्रेजों के हाथ में राजसत्ता आई हिन्दुस्तान को उनके लंकाशायर के कारखाने का बना हुआ माल हमारे हाथ के बने हुए कपड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। 50 फीसदी उन्होंने टैक्स लगा दिया, हिन्दुस्तान के माल पर इस हैण्डलूम प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट पर। तब भी आता रहा। सौ फीसदी लगा दिया, तब भी मालदार घरों की महिलाआ ने हिन्दुस्तान के बने हुए कपड़े को बेहतर समझा लंकाशायर कारखाने के बने हुए माल के मुकाबले।

एक पुस्तक ''भारत में अंग्रेरी राज्य'' पंडित सुन्दर लाल की लिखी हुई है, उसे चालीस साल पहले लिखा था शायद पचास साल पहले। उसमें उन्होंने लिखा है कि 1817 में एक कानून बनाया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि हिन्दुस्तान के हाथ के बने हुए कपड़े को जो इंग्लैण्ड में पहनेगा, उसको सजा मिलेगी। इस तरह नष्ट हुआ वो हैण्डलूम। करीब–करीब बाहर जाना बंद, अन्दर रहे। इसी तरह मैंने कहा कि सारे ही काम हाथ से तो चलते थे। मुझे नहीं मालूम है कि हरियाणे में, पंजाब में, मेरे ख्याल से तो सारे देश में डिस्ट्रिक गजेटियर अंग्रेजों ने तैयार करवाये थे। 1870 से लेकर 1885 तक। अपने–अपने जिले का डिस्ट्रिक गजेटियर उठाकर पढ़ो। उसमें यह मिलेगा आपको कि फलां कस्बे में यह चीज बनती थी, फलां कस्बे में यह चूड़िया बनती थीं, फला कस्बे में ये टाली बनती थी, फलां कस्बे में यह काम होता था, आज उन कस्बों में वह काम नहीं हो रहा है। आज बहुत से कस्बे उजाड़ हो गये हैं। क्योंकि उनकी दस्तकारी छिन गयी। अंग्रेजों के कारखानों के जरिये किसने छीन ली? क्योंकि, फिर दोहराता

हूँ कि मशीन से बने हुए माल का फायनेंशियली कम्पटीशन नहीं कर सकता हाथ का बना हुआ माल। वो सस्ता होगा।

मेरे मित्र अभी आये थे वो कह रहे थे कि खादी का काम या वह काम जो हाथ का है, दस्तकारी का, उद्योग–धंधों का तभी पनपेगा जब हमारे यहां स्वदेशी की स्पिरिट पैदा हो, जो गांधी जी ने पैदा की थी। बहुत हद तक वह सही कहते हैं। लेकिन मेरी नकिस राय में केवल इससे काम नहीं चलेगा। हम को कानून ही बनाना पड़ेगा। वरना सद्भावना के कितने ही व्याख्यान दीजिए (तालियां) और कितने ही समारोह कीजिए और गवर्नमेंट कितना ही रुपया लगा दे, आपकी मंशा पूरी नहीं होगी। तो कानून बनाना पड़ेगा, तब वो चीज पनपेगी। अब मुझसे लोग कहते हैं कि साहब आप की जो यह राय है कि कपड़ा यहां के कारखानों का बना हुआ विदेश में जाये, भयानक भी है। तो कपड़े की कमी हो जायेगी। छह महीने कमी रहेगी, नाना–नानी जो कपड़ा पहना करते थे, उससे दस गुना तो हमारी बहुओं पे, लड़कियों के ट्रंकों में भरा पड़ा है सब। (तालियां) नहीं है ये बात। कभी–कभी नम्बर नहीं आता है साल में एक दफा पहनने का। यही लड़कों का हाल है। और हमारे यहां तो क्लाइमेट, जलवायु परमात्मा ने दी है कि शायद दिसम्बर–जनवरी के अलावा कपड़े की कोई बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं। अब धीरे से सब बन जायेंगे।

अगर हमें अपने देश के मसले को हल करना है और सबसे बड़ा मसला मैं मानता हूँ बेरोजगारी का। तो उसके लिए ड्रास्टिक सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। ये जो कलकत्ते शहर, बम्बई शहर, मद्रास शहर में ट्रेन लाईन खिंच गयी हैं दिल्ली को, सारे भारत माता के वक्षस्थल को चीरती हुई, आप समझो कि अंग्रेजों ने हमारे लिए बनाई थी, नहीं। अपने कारखाने के माल को हिन्दुस्तान के कोने–कोने में, घर–घर पहुंचाने के लिए उन्होंने बनाई थी। और नतीजा हुआ कि सारे हिन्दुस्तान की सब कॉटेज इंडस्ट्री खत्म हो गयीं। और जो थोड़ी–बहुत बची थी, उसको हमारे दोस्त खत्म कर रहे हैं, हमारे लीडरान और हमारे सहयोगी। उन्होंने यार्कशायर, लंकाशायर के कैपटलिस्ट के हक में किया था, हम अपने कैपटलिस्ट के हक में। अपने थोड़े–बहुत जो उद्योग–धंधे बचे हैं, उनको आज खत्म कर रहे हैं। वो गरीब आदमी कंपीट नहीं कर सकता कारखाने के माल से। फिर कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांस्ट्रेशन नहीं, स्टेकुचरी, कानून के जरिये आपको यह हदबंदी करनी पड़ेगी कि ये चीज छाटे पैमाने पर बनेगी, ये चीज मशीन के जरिये बनेगी और मशीनों में यह भी चीज छोटी मशीन से बनेगी, वरना यह पनप नही सकते, रह नहीं सकते। तो हम टाटा, बिरला के लिए दूसरे उद्योग का, अहमदाबाद की मिल्स के लिए शोलापुर के मिल्स ऑनर के लिए हम उसकी रक्षा नहीं करना चाहते। क्या बात है? सन् 76 में एक ''जर्नल ऑफ डेवॅलपमेंट स्टडी'' शायद उसका नाम है, मैंने एक जगह उसका हवाला पढ़ा।

(भाषण की रिकॉर्डिंग अधूरी है)

इन 17 साल के अनन्तर 13 फीसदी से खेती करने वालों की तादाद रह गई चार, जबकि हमारे यहां खेती करने वालों को तादाद बढ़ी है और दूसरा पेशा करने वालों की तादाद घटी और देश गरीब हो गया। तो वो जो साढ़े दस फीसदी आदमी थे, उनमें से आठ, साढ़े आठ प्रतिशत आदमी कहां चले गये और उनकी औलाद, उसको जमीन की कमी नहीं थी, सब ने हल की हथकी पकड़ी, खेती की। उसक लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1931 की मरदमशुमारी की रिपोर्ट पढ़ो उससे जाहिर होगा कि आधे आदमी जो पहले दूसरा

पेशा करते थे, उन्होंने खेती करनी शुरू की। नाम ऐसे लिखे हैं उसमें– किसी गांव को देशो कि नाम हीरालाल, बाप का नाम रामलाल, कौम कुम्हार, पेशा खेती। उसकी कौम बता रही है कि उसके बाप–दादे खेती किये थे। आबादी 18 करोड़ थी 1857 में आपके देश की। अब बंगलादेश और पाकिस्तान को मिलाकर हो गयी 85 करोड़। उस वक्त जमीन थी। बेरोजगार लोगों ने हल की हथकी पकड़ी। आज वो जमीन भी इन लोगा के लिए मौजूद नहीं है। और फिर आज एजुकेटेड एम्पलॉयमेंट का सवाल है, जो उस वक्त नहीं था। पढ़ा–लिखा शिक्षित बेरोजगार लड़का खेती नहीं करता। उनका एक ही इलाज है– रोजगार। नॉन–एग्रीकल्चरल ऑक्युपेशन। दूसरा इलाज कोई है ही नहीं।

मुझे देर हो रही है। बस एक बात कह कर खत्म करना चाहता हूँ। ये इनके कोहली साहब के अधिकार क्षेत्र में कोई गांव सुल्तानपुर मैंने सुना है, देखा नहीं। उसमें फैक्टरी लगी हुई है प्री–फेब्रीकेटेड हाउसिंग फैक्टरी। बना–बनाया मकान, निर्माण करने की कोई जरूरत नहीं। वो फैक्टरी चली नहीं है और परमात्मा करे न चले। (हंसी)। अगर वो चल जाती और आपको मकान बनाना हो– न लुहार की जरूरत, न बढ़ई की जरूरत, न राज की जरूरत, ईंट पाटने वाले की जरूरत, न ईंट ढोने वाले की जरूरत, न दुकानदार से सीमेंट खरीदने– कोई जरूरत ही नहीं। ऑर्डर दे दीजिए कि इतनी लम्बी दीवार, इतनी चौड़ी, इतनी ऊंची, ऐसी छत है, ट्रक में भरकर आपके यहां आ जायेगा (हंसी)। क्यों साहब, हमारे जिन उन साथियों ने, मिनिस्ट्री ने उस जमाने में, जिन्होंने इस फैक्टरी को तय किया, वो देश की हालत को कैसे भूल गये। अगर मशीन से मकान बनने लगे, तो करोड़ा आदमी तो बेरोजगार हो जायें। इस गैर अक्लमंदी को मैं मूर्खता नहीं कहता हूँ, कहीं नाराज न हो जायें मेरे पुराने कांग्रेस के साथी।

आखिर कोई क्या कहे! एक तरफ कह रहे हैं बेरोजगारी बढ रही है, कैसे कम की जाये और दूसरी तरफ अपनी तरफ से बेरोजगारी पैदा करने के सारे काम इन लोगों ने किये। क्यों साहब, ताजमहल तो हमारे कारीगरों ने हाथ से बना दिया था, इजिप्ट के पिरामिड हाथ से बना दिये गये थे, पिछले युद्ध में बर्मा से चीन को सड़क लोगों ने हाथ से बना दी थी, कोई मशीन नहीं थी। तो हाथ से हमारे मकान आज क्यों नहीं बन सकते? आदमी की तीन आवश्यकताएं हैं सबसे बड़ी भोजन, कपड़ा और मकान। बेकरीज भी लग गई गवर्नमेंट की। मशीन, यंत्र से रोटी बनाने वाली क्यों? पुराने लोग छोटी–छोटी दुकानो पर बैठे हुए, आप अपना आटा दे दो। आपके आटे से वो डबलरोटी, बिस्कुट आदि बना देते थे। लेकिन गवर्नमेंट बेकरी ने हजारों–लाखों आदमियों को बेरोजगार कर दिया। कारखाने से बने हुए कपड़े, कारखाने से बने हुए मकान बनाने का स्वप्न। क्या करें, देश की बदकिस्मतो है और मैं कुछ नहीं कह सकता। तो खैर, समय मैंने बहुत ले लिया, छह बजे पहुंचना है। तो अब मैं यह चाहता हूँ कि जो काम शुरू किया है हमारे खादी कमीशन के दोस्तों की मदद से भानुप्रताप सिंह जी ने, मेरी परमात्मा से यह प्रार्थना है कि खादी कमीशन के मेरे दास्तों को और भानुप्रताप सिंह जी को और उनके सहयोगियों को और उन सहयोगियों में कोहली साहब को भी गिनता हूँ, इन सब को और खुराना साहब यहां बैठे हैं, इन सबको परमात्मा ऐसी बुद्धि दे दे, और बुद्धि से भी ज्यादा गरीब आदमी के लिए ऐसा दर्द दे कि आखिर ये कामयाब हो जायें इस स्कीम में।

––––––000–––––